distribution system. Based on the report of the Central Team and recommendations of the High Level Committee on Relief thereon, a ceiling of expenditure of Rs. 29.28 crores has been approved for drought relief in Kerala. In addition to this, Rs. 2.75 crores for completion of identified irrigation projects and Rs. 10.50 lakhs for increasing vegetable production have also been approved under drought relief programmes.

T.V. tower behind Taj Mahal

39. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state;

(a) whether it is a fact that T.V Tower behind the Taj Mahal is belittling the beauty of Taj Mahal;

(b) whether Government have received such type of complaints from tourists;

(c). if so, what steps Government propose to take in this regard including the shifting of T.V. Tower; and

(d) if T.V. Tower is to be shifted, by when it is likely to be shifted?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): (a) and (b) It has been noticed that the Agra T.V. Tower, be-ing visible from some positions in Taj Mahal complex, interferes with its overall scenic view.

(c) It has been decided to shift the relay centre to an alternative site.

(d) The work is likely to be completed during 1988-89.

Housing as an industry

40. SHRI PRAMOD MAHAJAN; Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 2379 given in the Rajya Sabha on 28th November, 1986 and state what are the details of the proposal to declare housing as an industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): The proposal is under consideration of the Government.

राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन

41. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुईं और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में गैर सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप मे सभी स्तरों पर नामि-निर्देशित करने के मामले में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी-अनुभाग को छोड़कर उन अनुभागों के नाम क्या हैं जहां शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है और वहां ऐसा किन तारीखों से हो रहा है तथा जहां हिन्दी को अभी तक अपनाया नहीं गया है उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम के पारित होने के 24 वर्ष बाद भी तथा पिछले 10 वर्षों के वार्षिक कार्यक्रम तैयार किये जाते रहने के बाद भी मंत्रालय स्तर से लेकर निचले स्तर तक राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) कृषि मंत्रालय के सभी विभागों अर्थात् कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा उर्वरक विभाग के लिये एक संयुक्त हिन्दी सलाहकार

समिति है। इस कैलेण्डर वर्ष के दौरान अब तक इस समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। जहां तक राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में गैर सरकारी सदस्यों का पर्यवेक्षकों के रूप में नामांकन करने का संबंध है। इस मुद्दे की पहले ही छान-बीन की जा चुकी है। लेकिन इन समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करना संभव नहीं पाया गया क्योंकि ये पूर्णतया आंतरिक विभागीय समितियां हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) धारा 3(3) सहित राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के विभिन्न प्रावधानों तथा वार्षिक कार्यक्रम का, जहां तक संभव हो सके, उत्साह और निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है। सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वशासी निकायों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यान्वयन पर संबंधित विभागों द्वारा कड़ी निगाह रख जाती है और वैयक्तिक निरीक्षण आदि किये जाते हैं तथा जहां कहीं जरूरी समझा जाता है, कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए निवारक उपाय किये जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन

42. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुईं और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में सभी स्तरों पर नाम-निर्देशित करने के मामले में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अनुभाग को छोड़कर उन अनुभागों के नाम क्या हैं जहां शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है और वहां ऐसा किन तारीखों से हो रहा है तथा जिन्दी को अभी तक अपनाया नहीं गया है उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम के पारित होने के 24 वर्ष बाद भी तथा पिछले 10 वर्षों से वार्षिक कार्यक्रम तैयार किये जाते रहने के बाद भी मंत्रालय स्तर से लेकर निचले स्तर तक राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को कार्यान्वित न किये जाने के विषय के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री **एच०के०एल० भगत**) : (क) चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की अप्रैल, 1987 में एक बैठक की गई थी। एक अन्य बैठक के शीघ्र ही किए जाने की सम्भावना है। फिलहाल विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति में गैर-सरकारी व्यक्तियों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

(ख) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के सभी अनुभागों और कार्यालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे कुछ ऐसे विषयों का चुनाव कर लें जिनमें सभी कार्य हिन्दी में किया जाना होगा। तदनुसार, अनुभागों और कार्यालयों ने इस प्रयोजन के लिए कुछ विषयों को चुन लिया है।

(ग) मंत्रालय के दोनों विभागों और उनके प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सम्बद्ध कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबंधों कार्यान्वित किया जा रहा है।

परवल की खेती

43. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार, मुंगेर जिला के जमालपुर प्रखण्ड के बिन्दा-दियारा क्षेत्र में परवल की बड़े पैमाने